[Shri Narendra Singh Mahida]

there should be a forum for farmers, a forum for the upliftment of rural areas. I look forward to the day when we in this House, leaving aside party ideologies, can get together and if the Government is not listening to us, hammer the Government and make them implement the irrigation projects, the fertiliser projects, projects for providing drinking water, etc.

With these words, I take note of this motion and I hope the Government will pay more and more attention to the upliftment of the rural areas.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I may be allowed to move my substitute motion I want to go, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will take it as moved.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I beg to move :

That for the original motion, the following be substituted, namely :—

"This House, having considered the food situation in the country, recommends that—

(a) more quota of wheat and rice should be allotted to Delhi for rice-eaters and labourers;

(b) more quota of sugar should be allotted to Delhi;

(c) arrangements should be made to supply coarse grains adequately to Delhi; and

(d) restriction on the movement of foodgrains except wheat and rice should be removed immediately in view of the bumper crop this year with the ultimate aim of abolishing food zones." (7)

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, agriculture is the basic industry in this country. It can give us adequate food for the people, raw materials for industry and full employment. Even then, food shortage has become a chronic phenomenon in this country bringing in its trail periodical famine and misery.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may resume his speech on the next occasion.

17.29 hrs.

*

GRANT OF DEARNESS ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT PENSIONERS

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पेंशनर्स का मामला है उसको इस सदन में पिछले कई वर्षों में कई बार उठाया गया है। पिछले पांच सालों में, मैं ने अभी पता लगाया, 68 बार इस सदन में पेंशनर्स के मसले को ले कर प्रश्न पूछे गये हैं और 30 या 40 बार अलग अलग मामलों की बहस के समय इसको उठाया गया है। मगर अफसोस इस चीज का है कि इतनी बार इस मसले पर यहां प्रश्न पूछते हुए भी और बहस चलाते हुए भी, सरकार की ओर से पेंशनर्स के मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखलाई जाती है।

एक ही मांग पेंशनर्स की ओर से की जाती है कि जो पेंशन उन्हें दी जाती है, उसके साथ उन्हें मंहगाई भत्ता दिया जाये। मंहगाई भत्ता किस रूप में दिया जाये, इसके बारे में कोई ठोस बात भले ही न आई हो, लेकिन इस के बारे में उनका कहना इतना ही है कि जब चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं और दूसरे कर्मचारियों को आप महंगाई भत्ता देते हैं, तो उन लोगों ने कौन सा पाप किया है कि आप उनको महंगाई भत्ता देने से इन्कार करते हैं। पिछले पांच छः सालों में इन पेंशनरों के प्रतिनिधिमंडल किसी न किसी तरीके से जो तीन प्रधान मंत्री हो चुके हैं उनसे मिलते रहे हैं। 1961 के सितम्बर महीने में प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से पेंशनरों का शिष्टमंडल मिला था। उसके बाद शास्त्री जी से मई 1965 में उनके कुछ प्रतिनिधि मिले थे। अभी सितम्बर 1966 में श्रीमती नेहरू गांधी से पेंशनरों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था और उसने खास तौर पर अपने इस महंगाई भत्ते की मांग रखी थी।

---

*Half-An-Hour Discussion.

मजे की बात यह है कि तीनों प्रधान मंत्रियों की ओर से सभी प्रतिनिधि मंडलों के साथ पेंशनरों की मांगों के बारे में सहानुभूति व्यक्त की गई है। जब सितम्बर 1961 में नेहरू जी से इस प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई थी तब नेहरू जी की ओर से यह कहा गया था कि यह मामला मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के पास भेज रहा हूं और उनकी ओर से कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। शास्त्री जी ने 1962 के अप्रैल महीने में पेंशनरों का जो एक संगठन है, भारतीय पेंशनर समाज के नाम का, उसको एक पत्र भी लिख कर भेजा था कि तीन सौ रुपये से कम पेंशन पाने वाले जो लोग हैं उनको कुछ मंहगाई भत्ता देने की हम व्यवस्था करेंगे। 1-10-1963 से शास्त्री जी के इस आश्वासन को पूरा करने की नौबत तो आ गई। शास्त्रीजी से इनकी जो मुलाकात हुई थी और जो बात शास्त्री जी ने उनको कही थी वह पेंशनर्ज जनरल करके जो अखबार पेंशन पाने वालों की ओर से चलाया जाता है उसके जून 1965 के अन्त में छपी थी। इसमें कहा गया है :

> "As for the appointment of Pension Commission he did not think it possible at present. The Prime Minister, however, promised to examine with sympathy the points raised especially the question of dearness allowance and medical relief,"

यह तो लालबहादुर शास्त्री जी की बात हुई। अभी प्रधान मंत्री श्रीमती नेहरु गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। तब उनकी ओर से जो कहा था वह सितम्बर 1966 के अंक में छपा है। वह मैं पढ़ रहा हूं :

> "You have waited so long. Wait for a few months more when our financial position is expected to improve."

पेंशनर भी बेचारे इतने भोले लोग हैं कि वे अखबार में लिखते हैं :

> "This short and sweet remark convinced all those who heard her of her sincere desire to help and that it was not the stereotyped official evasiveness."

यह तीनों प्रधान मंत्रियों के आश्वासनों की बात हुई।

जब-जब यह मसला सदन में या सदन से बाहर उठाया गया है तब-तक सरकार की ओर से इन्कार करने का ही काम हुआ है। इसका कारण यह है कि पेंशनर बेचारे ऐसे हैं कि उनका कोई शक्तिशाली संगठन नहीं है, वे कोई सख्त आन्दोलन नहीं कर सकते हैं ताकि सरकार पर दबाव डालने का, सरकार को ठिकाने पर रखने का काम हो सके। जो सरकारी नौकर हैं चाहे वे सचिवालय में हों या सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में हों, संरक्षण विभाग में हों या पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में हों या कहीं भी हों जब कभी वे सरकार से मांग करते हैं तो केवल तनख्वाह बढ़ाने की या मंहगाई भत्ता बढ़ाने की ही मांग करते हैं लेकिन अपनी जो उनकी जिन्दगी 55 साल या 58 साल के बाद की है, रिटायर होने के बाद की जिन्दगी जो है, उसके बारे में जैसा उनको सोचना चाहिये, वैसा वे सोचते नहीं हैं। उस लिहाज से वे नहीं सोचते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि रिटायर होने के बाद एक लाचारी की भावना उनमें आ जाती है जोकि हमें आज भी दिखाई पड़ती है।

जो बड़े लोग हैं, हाई कोर्ट के जज हैं या आई० सी० एस० अफसर हैं या दूसरे बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको रिटायर होने के बाद सिर्फ पेंशन के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता है, उनको सरकार कई कमिशनों में बिठा देती है, किसी को विदेशों में राजदूत बना कर भेज देती है या किसी और काम में लगा देती है। इससे आज जितना उनको वेतन मिल रहा होता है बाद में पेंशन मिला कर उससे भी ज्यादा आमदनी उनकी होने लग जाती है। सौ डेढ़ सौ या दो सौ पाने वाले तबके के जो लोग हैं उनके बारे में जो विभागीय अधिकारी हैं वे भी नहीं सोचते हैं और न ही सोचने के लिए तैयार होते हैं। अगर मंत्रियों के लिए पेंशन का इंतजाम किय जाए तो हो सकता है कि इन बेचारे गरीब पेंशनरों के बारे में भी कहीं

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

सोचने का काम हो। लेकिन मिनिस्टर्ज को पेंशन देने की बात नहीं होती है। उनको तो यह लोग ही उनके पदों से हटाते हैं या सदन उनको डिसमिस करता है। इसके अलावा और कोई रास्ता इनके लिए नहीं रहता है।

पेंशनरों की आज हालत यह है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। श्री मोरारजी देसाई जैसे लोग भी हर मामले में लोगों को उपदेश देने का ही काम करते हैं। उनका दृष्टिकोण भी पेंशनरों के बारे में यही है कि वह पेंशनरों को अगर पांच रुपये अधिक दे देते हैं तो सोचते हैं कि यह वह उन पर मेहरबानी कर रहे हैं। पिछले दस सालों में एक बार पांच से लेकर दस या साढ़े बारह रुपये तक बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। वह भी मेहरबानी के तौर पर किया था। इसलिए नहीं किया था कि पेंशनर इसके अधिकारी हैं। आप भी इंसान हो। एक आदमी 25 साल या 35 साल देश की सेवा में लगाता है। क्या बुढ़ापे में आप उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं? सरकार की हैसियत से, समाज की हैसियत से यह जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं, इसको कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेहरबानी के तौर पर सब कुछ किया जाता है।

श्री जगन्नाथ दास का एक वक्तव्य मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वह सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। सेंट्रल पे कमीशन के अध्यक्ष भी वह रह चुके हैं। मंत्री महोदय की जानकारी के लिए मैं खास तौर पर यह उनके सामने पढ़ देना चाहता हूं। वह कहते हैं:

> "Pension is an entitlement such as pay of the working employees and it is integrally connected with pay. Therefore, similar considerations as for pay should be applied to the pensioners, not as a matter of grace but as a matter of obligation by Government."

जगन्नाथ दास का कहना यह है कि यह सरकार पर एक अबालीगेशन है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको समझे। पेंशनर्ज का इस वक्त कोई संगठन नहीं है। इस वास्ते उनको परेशान करने वाला जो तरीका चलता है वह तरीक बन्द होना चाहिये।

यह मामला सैकिंड पे कमीशन के सामने भी उठाया गया था। चूंकि यह मसला पेंशनरों की ओर से, उनके संगठन की ओर से और कर्मचारियों के जो संगठन हैं उनकी ओर से भी वे कमीशन के सामने पेश हुआ था इस वास्ते पे कमीशन ने पेज 453 पर 29 नम्बर के परिच्छेद में जो कुछ लिखा है उसको मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:

> "It has been asked by some former employees, as also on behalf of those who are still in service, that there should be adjustment of pensions to meet increases in the cost of living, and it is argued that equity demands that the real value of pensions, particularly of the smaller ones, is maintained. Attention has been drawn to the well-known fact that pensioners are among the sections of the community which suffer most in a period of inflation, and the problem is, therefore, one with moral and human aspects. Those who had retired before this Commission was set-up are beyond our terms of reference; but retirement benefits being among the important conditions of service we are concerned with the question of adjustment of pensions of those who are in service and who, on retirement, may find the real value of their pension substantially reduced because of increase in the cost of living. We recognise that the claim for relief in such cases would not arise on contractual grounds; but we think that on humane grounds relief should be allowed in cases in which the pension does not exceed Rs. 200 per mensem. We leave it to Government to determine the rate of relief."

हालांकि इस पे कमीशन ने यह कहा था कि कांट्रैक्चुअल ग्राउंड्ज पर वह मानने के लिए तैयार नहीं है लेकिन मैं उनकी इस बात को कतई कबूल नहीं कर सकता। चूंकि वे एक जमाने में सरकारी कर्मचारी थे और सरकारी कर्मचारी रहते हुए उनको महंगाई भत्ते का अधिकार मिला है, इसलिए सामाजिक न्याय देने की दृष्टि से पेंशनरों के भरण पोषण की

जिम्मेदारी सरकार की जरूर हो जाती है। इस वास्ते महंगाई भत्ता उनको देने से सरकार को इन्कार नहीं करना चाहिये।

एक महत्व का जुमला मैं पेश करना चाहता हूं। पेंशन मंत्रियों को नहीं दी जाती है। लेकिन हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति को पेंशन दी जाती है। 1952 में राष्ट्रपति की पेंशन के बारे में एक विधेयक इसी सदन में पेश हुआ था। उसमें कहा गया था कि पंद्रह हजार रुपये सालाना राष्ट्रपति को रिटायर होने के बाद पेंशन के रूप में दिये जाने चाहियें। उसके बाद 1962 में राष्ट्रपति की पेंशन अलग से बढ़ाने की बात तो नहीं हुई लेकिन अधिक पैसा उनको देने की व्यवस्था कर दी गई। 1962 से हर महीने एक हजार रुपया ज्यादा राष्ट्रपति को पेंशन में अधिक देने की व्यवस्था कर दी गई और कह दिया गया कि यह पेंशन नहीं है बल्कि सैकटेरियल असिस्टेंस के लिए एक हजार रुपया महीना दिया जाता है। साथ ही साथ 1962 के नए विधेयक में राष्ट्रपति के लिए दवा दारू का इंतजाम भी सरकार की ओर से किया जाए, यह भी इंतजाम कर दिया गया। उस वक्त इस विधेयक पर इसी सदन में बहुत बहस चली थी। शायद आपने भी उस बहस में काफी हिस्सा लिया होगा और उस वक्त जब यह बहस चली तो लाल बादुर शास्त्री जी ने उस विधेयक को यहां पर पेश किया था और उन्होंने बड़े महत्व की बातें कही थीं वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं ताकि मंत्री महोदय आज भी पेंशनरों के प्रश्न पर जवाब देने के पहले काफी गंभीरता से सोचें कि इसी सदन में इन पेंशनरों के बारे में कैसी कैसी तात्विक बातें कही गई हैं :

"Very recently, a representation of the Bharat Pensioners' Samaj was forwarded to me and a copy also came to me direct from the Prime Minister."

यह शास्त्री जी की तकरीर है अध्यक्ष महोदय।

"I immediately looked into it and I have made my own recommendations. I myself felt that something has to be done for the pensioners. Conditions have changed. Prices have gone up. In these circumstances, if possible, something should be done for the Government pensioners. We in the Home Ministry have considered over the matter. We have not finalised it, yet we are in the process of thinking over or considering it. We have taken it up with the Finance Ministry. I have had talks directly with the Finance Minister also.

In regard to medical aid for pensioners, for all the retired employees of the Central Government who live in Delhi, we have already passed orders that they will be included under the contributory health service scheme. That is, they will be able to get the same facility as the employees working in the Government get just at present.

So, it is not correct to say that we do not think of the smaller people or of those who are the weaker elements in society. It is not correct. As I have just now referred to Government pensioners, the House can very well judge how we deal with these matters when they come to our notice. It does not make any difference for us whether a proposal concerns a big man or an ex-President or an ex-Minister."

तो मेरा इतना ही निवेदन है इस सदन से और मंत्री महोदय से कि पेंशनरों की जो मांग है उस मांग को तात्विक रूप से हमेशा आप कबूल करते रहे हैं, तीन प्रधान मंत्रियों ने कबूल किया है, राष्ट्रपति के पेंशन पर बहस होते समय आप ने सैद्धांतिक रूप से माना है; आज जब कि चीजों के दाम बढ़ गए हैं और यह समाज का वह तबका है जिन्होंने अपनी सारी जिन्दगी देश की और समाज की सेवा में लगायी है; तो उनको सड़कों पर भीख मांगने की हालत में आप न रखें, क्योंकि वह हड़ताल करने की हालत में नहीं हैं या प्रदर्शन करने की हालत में नहीं हैं इसलिए उनको इस लाचारी की हालत में न रखें जिससे उनकी जिन्दगी बर्बाद हो जाय और महंगाई जो उनके पेंशन में जोड़ने

[श्री जार्ज फरनेंडीज]

की बात है उसको जल्द से जल्द उनके प्रतिनिधियों से मिल कर तय करें। इतना ही मुझे कहना है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would like to point out to the Members—already we have pointed out, not only once but on several occasions—that under the new rule... ...

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : We know the rule. We have committed a mistake and we apologise for that.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Only one Member, Shri Lobo Prabhu had given notice and he is absent now. Then, I have got four or five slips from different Members. Ignorance of the Rules cannot be an excuse. Even if you give an apology, it will not be accepted in any court of law. Even then, as the matter is very vital and most of you, who have written to me, take interest in such matters I will strictly allow only one question and no speech. Of course, I must warn you, those who are participating today will take note that next time even with an apology and excuse it will not do.

SHRI S. M. BANERJEE : We shall never comit the mistake.

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि जब हालत इतनी खराब हो गई है और इस पर चर्चा हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर के साथ, एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ और उनको आश्वासन दिए गए हैं, उसी तरह पे कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, उनका बयान यहां आया है तो क्या मंत्री महोदय इस सदन को यह आश्वासन दे सकते हैं कि इसके बारे में कोई कमीशन अप्वाइंट करेंगे ?

श्री नीति राज सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो उत्तर दिए गए हैं उनके अनुसार रेलवे को छोड़ कर केन्द्र के 6 लाख 8 हजार 778 पेंशनर्स हैं। उन को जो पेंशन दी जाती है वह 24 करोड़ 22 लाख 61 रुपये हैं। उनकी मांगों में जो महंगाई की मांग है। पर शासन ने 58 में 100 रुपये तक पेंशन पाने वालों को दस रुपया और 1-10-1963 को 200 रुपये तक पाने वालों को 5 से 10 रुपये बढ़ाया है जबकि महंगाई कई गुना अधिक बढ़ी है। तो क्या मंत्री महोदय इसके ऊपर विचार कर उत्तर देंगे कि इसकी बावत वे क्या विचार कर रहे हैं ? ऐसा उत्तर न दें कि हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, यह उत्तर हम नहीं चाहते हैं। हम कोई सहानुभूति का उत्तर चाहते हैं।

SHRI S. M. BANERJEE : I would like to know, in view of the assurances given by the three Prime Ministers and also in view of the assurance given here, in this House, by the ex-Finance Minister, Shri T. T. Krishnamachari, that the Government will consider their three demands, that is, commutation, grant of dearness allowance and grant of medical aid, whether Government has given consideration to all these things. About the C.G.H.S. which was to be introduced in the case of pensioners in Delhi, even that has not been done. I would like to know from the Minister whether, in view of the fact that recently the pensioners came here and paraded in the streets of Delhi—we cannot expect our fathers to parade like this—these demands, specially that of dearness allowance, will be considered by the Government.

श्री भीचंद गोयल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, में मंत्री महोदय की सेवा में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज समाज की स्थिति बिलकुल बदली हुई है। आज रिटायर होने के बाद कोई भी पेंशनर इस स्थिति में नहीं है कि उसके बच्चे उसको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देते हों। इस कारण इस बात का विचार करते हुए कि जब महंगाई इस तेजी से बढ़ रही है और उनको आलटरनेटिव एम्प्लायमेंट कहीं और मिल नहीं सकता, उनके बच्चे उनकी सहायता कर नहीं सकते तो आज क्या सरकार गंभीरता से इस बात पर विचार करेगी कि उनको यह महंगाई भत्ता

मिले और विशेष कर उनको जो स्वास्थ्य की सहायता है, फ्री मेडिकल एड, वह निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों की तरह से उनको भी मिलनी चाहिए क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें यह आवश्यकता और लोगों की तुलना में ज्यादा बढ़ जाती है ?

DR. RANEN SEN (Barasat) : In view of the fact that in the last Pay Commisson's Report, the increased dearness allowance or some increase in the emoluments of pensioners was recommended, in view of the fact that they are in a difficult position due to high price rise, and in view of the fact that, I should say, Government have made certain commitments, though there is financial difficulty for the Government of India, would the Government of India consider their demands in the spirit of natural justice so that the pensioners' grievances are minimised and, at least with a little amount of dearness allowance, they are able to make both ends meet ?

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : Will the hon. Minister kindly give some assurance to the organisation called the Bharat Pensioners Samaj that he accepts the principle of negotiation himself and also for the State Governments because there is an unfortunate instance of a Chief Minister of a State who is reported to have told the delegation of pensioners that if the pensioners find it difficult to carry on, why don't they commit a suicide ?

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूं कि आज जब कि देश के अंदर समाजवाद के नाम पर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं और विभिन्न प्रदेशों के अन्दर वृद्ध लोगों के लिए कुछ पेंशन का और कुछ और भत्ते आदि का विचार कर रहे हैं तो यह लोग जिन्होंने देश की सेवा की और जिन्होंने सेवा के बाद अपनी पेंशन अर्न की, उन लोगों को इस महंगाई के जमाने में जैसे औरों को हम कुछ राहत दे रहे हैं क्या उनका अधिकार नहीं है कि उनको कुछ राहत मिले ?

श्री रबी राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि यह कम से कम जो वृद्ध हैं और 70 साल की उम्र के हैं तो उनके लिए उनको कुछ न कुछ इलाज मिलना चाहिए, कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि उनको कुछ पेंशन मिले और डीअरनेस एलावेंस मिले ?

SHRI S. KUNDU (Balasore) : The tragedy with these pensioners is that they are just like orphans; they do not have any father or mother. Therefore, their case is always neglected. What I would like to know from the hon. Minister is this. This question has two aspects, the one is moral and the other is legal. It is moral because, since these people have worked for so many years and have spent best of their time in serving the country, after having served the country for so long, nobody looks after them. It is legal because this is within the contract of service rules that he is entitled to a pension. When you give pension, let us see what is its worth. For instance, a person who got his pension of Rs. 100, 20 years back. What is the value of those Rs. 100 to him today ? It is worth only Rs. 14 twenty years after. Since you had entered into some contractual obligation to pay him Rs. 100, you must give him not Rs. 14, but an amount equal to Rs. 100 twenty years back.

Last time when the Government recommended D.A., we were very happy—of course, different views were there, but generally we were happy—that some government servants got some D.A. At that time, it was the moral duty of the Government to fix D.A. for the pensioners also. But they have not done it. I would, therefore, like to know from the Minister—let not Minister say 'no'; then it will be very unfortunate because the other three Prime Ministers have given hope—whether he is going to consider giving them D.A. and if so, from which date it will be given to them and whether he will get the matter examined departmentally or through a Commission.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : My feeling is—and your feeling is also the same—that non-pensioners and pensioners make one integrated whole so far as service is concerned, especially so far as govern-

[Shri D. C. Sharma]

ment service is concerned. There should be no distinction made between those persons who work and those persons who have retired. Therefore, I would ask the Minister as to why it is that he does not give the pensioners the three facilities which have been described by many hon. friends, namely, the dearness allowance, free medical facilities and commutation. If he is not able to give them these, I think, we should have a Commission to go into the whole question so that the aspirations of those persons are satisfied.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I do not have much time and I should like to cover briefly the main points that have been made.

There was some reference to Rajen Babu, to the fact that he got secretarial assistance along with the pension of Rs. 1,000 per month. I am told that the secretarial assistance came within those Rs. 1,000 and not in addition to that. Because he is a very respected leader and something was said about him, I thought that it was my duty to set the records straight.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैंने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is putting the records straight.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : जब रिकार्ड खराब ही नहीं हुआ, तो स्ट्रेट क्या करेंगे । हमने सिर्फ विधेयकों के बारे में कहा है ।

SHRI K. C. PANT : Nevertheless, it is something which I thought that I should mention.

The Mover of this Half-an-Hour Discussion made a speech in which he made several points, which were repeated by the others. He said that if Ministers started getting pension, perhaps they would pay attention to that problem. I was wondering whether he was going to say next that the Members should also be given some pension, so that there would be all-round support for it....(*Interruptions*)

श्री एस० एम० जोशी : पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को मिलता है ।

SHRI K. C. PANT : I find that, even without that, there is ample support and I at least find mysef in considerable sympathy....(*Interruption*) Pension to whom ?

SHRI RABI RAY : To Dr. P. C. Ghosh.

SHRI K. C. PANT : If he survives the mechanisations of my friend, maybe he will get a pension.

AN HON. MEMBER : From the central coffer or from the State ?

SHRI K. C. PANT : From the coffers of the public.

Mr. Deputy Speaker, about this problem, so far as the principle of it goes, there can be no difference of opinion. We are all aiming at a welfare state. In aiming at a welfare state we all of us, I think, would agree that not only pensioners, but others beyond a certain age when they cannot earn for themselves, should get protection from the society. It is not a question of Government servants alone. It was said that Government servants serve society and the country. I agree they do. They certainly do and a right should be given to them. At the same time other sections of the society also do their bit.

SHRI S. M. JOSHI : They get under the contractual obligations.

SHRI K. C PANT : Yes, under the contractual obligations we do pay them pension. But the whole question is : one would like to have in this country more wealth. One would like to have greater production and one would like to be in a position where one could give to every single individual in this country the kind of social benefits which are to-day available in a country like Sweden or any one of the advanced socialist countries. It is one of the dreams of the founders of this country and so, anybody who counters this basic concept would be false to the ideals on which our Constitution is based. However, this is something that lies in the future when we reach that state of material well being where we can afford this. For the present we have

various systems. We have self-employed people who do not have any pensions. We have people who are unemployed and we have people who get provident funds after years of labour which is largely their own contributions. We have peolpe who get gratuity which lies in the field of grace. All these various systems are there. But among these the Government servants, by virtue of their contractual obligations, as has been said, are given pensions.

So, this is what exists in our country to-day and this has got to be accepted for what it is. It has been said that some of the ex-Judges are assigned certain duties. Well, I see the limitations of giving diplomatic duties to each and every person.

SHRI D. C. SHARMA : If you read the laws passed about Judges, you will find that no Judge will die without drawing a salary till the last second of his life.

SHRI K. C. PANT : Therefore, Judges are well protected. At least somebody in his age is very well protected. But nobody is debarred from working. No pensioner is debarred from working although I can well recognize that it is not easy to work.

Now, I do not want to go into the steps which have already been taken. Pensions have been revised once in 1958 and again in 1963. It was mentioned by some hon'ble Members. And in December 1964 medical facilities under the Central Govt. Health Scheme have been extended to pensioners in Delhi.

SHRI S. M BANERJEE : It is only in Delhi.

SHRI K. C. PANT : That is wha' I said. The increase in 1958 was Rs. 10 upto Rs. 50 and Rs. 12·50 upto Rs. 100 and then Rs. 5, Rs. 7·50 and Rs. 10 are the various slabs of increases. This is what has already been done in the last few years—that is upto 1963. It would be wrong on my part to suggest that the picture in 1963 was what it is to-day. It is very different. Prices have risen sharply in the last few years and there is no doubt that this has caused difficulty and it has caused difficulty to all people with fixed incomes. And if anybody tries to suggest that this is an easy situation for the pensioners, he is being dishonest. At the same time, ultimately to suggest that dearness allowance should be given to these pensioners at the rates at which Government servants are given, is a principle which suggests that they should be treated on par with serving Government servants. Now, with all respect I would suggest that the position of serving Government servants is different from that of the pensioners and the latter, in principle, are not eligible to the same concessions which are admissible to the serving Government servants. I think that is a principle which will be accepted by this House.

18 hrs.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : महंगाई भत्ते के बारे में हम इसको नहीं मान सकते। तनख्वाह के बारे में मानें।

SHRI K. C. PANT : The second point is that Government must necessarily give first priority to meet the demands of those who are now in service. All my friends have been for the last few months talking to Government about the needs of the Government servants who are now in service, and understandably so. This is the principle that has got to be recognised. If dearness allowance is given to pensioners at rates at which the Government servants are given dearness allowance today, then the dearness allowance will come to something more than the pension that they are getting today.

SHRI D. C. SHARMA : Let him appoint a commission.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आपका रुपया 17 पैसे हो गया है गये 20 सालों में।

SHRI K. C. PANT : Repetition will not strengthen the argument. Argument is strong enough. If I had the resources I would not need my hon. friend's persuation.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अगर मानते हैं तो कुछ तो दीजिये।

SHRI K. C. PANT : That is where he and I have got to understand each other. I have understood what he has told me and

[Shri K. C. Pant]

now he should try to understand what I am telling him. The resources position being what it is, every day we are criticised in this House by friends opposite for the condition of the economy in the country.

My hon. friend Shri George Fernandes waxes eloquent in saying 'Where have you brought the country during the last twenty years ? The country is bankrupt' and so on. But suddenly now he forgets all that he has said in another speech, and now he says that we should find money and give it. My hon. friends opposite should also recognise the difficulties of the present economic situation. They recognise that resources are scarce at the moment, and I am sure they will understand the difficulties in which Government find themselves in this matter.

A number of other suggestions were made, and I can go into all those suggestions individually but really they cover the same ground.

There are two points involved. I would like to ask Shri M. L. Sondhi who said that pensioners should go and commit suicide.....

SHRI M. L. SONDHI : I can give this literature to him.

SHRI K. C. PANT : For my personal information.

SHRI M. L. SONDHI : It is by the Chief Minister of a State.

SHRI K. C. PANT : He can give it to me later.

The other suggestion is that a commission should be set up.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Bhopal) : The Chief Minister may say anything, just as some suggestions have been made to encourage suicide to check-mate population growth. So, we cannot rule out such a statement.

SHRI K. C. PANT : As regards population control, I am an unabashed votary of population control. I am an absolutely unapologising and insistent votary of population control.

SHRI S. M. BANERJEE : Let him read the pathetic letter of a pensioner where he has said : 'Are the pensioners more dead than alive?', and has quoted the Chief Minister.

SHRI K. C. PANT : Let me complete what I was going to say. It is past six o' clock, and I do not want to trouble my hon. friends.

The only suggestion that has been made is that there should be a commission. We accept the suggestion if the commission could produce wealth. Where the difficulty is in finding resources, setting up a commission to make suggestions which cannot be implemented for want of resources is not statesmanship. Therefore, I would appeal to those who make that suggestion to understand that the difficulty is not one of intentions or of sympathy but of means.

18·05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 30, 1967/Agrahayana 9, 1889 (Saka).

M87LSS(CP)/67—GIPF.